Then, the other problem is that GAIL continues to collect transportation charges, even though it had recovered the capital cost incurred towards establishment of the transportation network for the existing power plants, instead of collecting charges based on the gas actually supplies by it. So, it is humbly requested that the Ministry of Petroleum should direct GAIL and ONGC immediately to supply gas to the four power plants in Andhra Pradesh, as per the agreement entered into by the parties. I also request the transportation charges should be collected based on the actual gas supply. This may kindly be treated as urgent and the needful may be done. Thank you.

Need for Pre-emptive Measures to Avoid Kargil-Like situation in future

श्री पी॰के॰ माहेश्वरी (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे "ताकि कारगिल न हो दोबारा, ऐसे कदम उठाएं", इस विशेष उल्लेख के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करने का मौका दिया है।

महोदय, माननीय रक्षा मंत्री ने सियाचीन में सेना की कटौती पर सहमति जताते हुए एक अहम सवाल पाकिस्तान से पूछा है कि वहां कारगिल की पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? सवाल देश की सुरक्षा, अखंडता तथा भावनाओं से जुड़ा है, क्योंकि देश एक भू-भाग मात्र नहीं है। सियाचिन में हर साल, उसकी रक्षा करते हुए, इतने जवान और अधिकारी भीषण ठंड से लड़ते हुए जान गंवा देते है, जितनी जानें किसी युद्ध तक में खोने की कल्पना नही की जाती। हर जवान दुश्मन से लड़ते हुए देश की सुरक्षा में शहीद हो जाने में गर्व महसूस करता है, परन्तु प्रकृति से जूझते हुए होने वाली मौत कहीं न कहीं कसक छोड़ जाती है। यद्यपि हम सदैव सियाचीन में सेना की कटौती के पक्षधर रहे है, फिर भी कारगिल के बाद छांछ भी फूंक-फूंक कर पीना चाहते हैं। हाल ही में नौसेनाध्यक्ष ने समुद्र में परमाणु सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आग्रह किया है, यह आंतरिक उथल-पुथल का संकेत है।

इसको समझते हुए सुरक्षा के बारे में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। हालांकि शासन ने एक सोचा समझा सीमित खतरा जम्मू कश्मीर में सेना की कटौती करके उठाया है ताकि हमारी सेनाएं सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दे सकें और आंतरिक गतिविधियों में शक्ति न गवाएं। प्रधानमंत्री जी की यात्रा के आधा घंटा पूर्व हुए आत्मघाती हमले के बाद भी हमने सेना की टुकड़ियों की वापसी को कार्यरूप दिया है और प्रधानमंत्री जी ने हमले के बाद भी इसे जारी रखने की अनुमति दी है लेकिन सावधानी बरतनी होगी।